आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 21.03.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रदेश की भाजपा सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे।
- केंद्र सरकार, वर्ष 2030 तक शत प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य के साथ पढ़ाई के दौरान स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के नामांकन के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगी।
- उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में आज हिमस्खलन की चेतावनी।
- प्रदेश में एस.आई.आर की तैयारियां तेज; प्रक्रिया में अब बूथ लेवल अधिकारियों की मदद के लिए आईटी वॉलंटियर्स भी तैनात किए जाएंगे।

जनसभा

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड की भाजपा सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज हल्द्वानी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

इससे पहले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल हल्द्वानी पहुंचकर सर्किट हाउस काठगोदाम में अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने एमबी इंटर कॉलेज मैदान में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसभा में आने वाले लोगों के लिए बैठने, पेयजल, साफ–सफाई और शौचालय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी को असुविधा न हो। साथ ही शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए रूट डायवर्जन प्लान तैयार कर उसका व्यापक प्रचार–प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए।

देशव्यापी अभियान

केंद्र सरकार बीच में ही विद्यालय छोड़ चुके बच्चों की पहचान करने और उन्हें दाखिला दिलाने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू करेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस कदम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2030 तक प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शत प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

समय सीमा बढोतरी

प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–पी.एम.जे.एस.वाई के तहत चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए समय–सीमा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने इस संबंध में निर्णय लिया है।

अब पीएमजीएसवाई–1 के अंतर्गत शेष देनदारियों के भुगतान और पीएमजीएसवाई–2 तथा पीएमजीएसवाई–3 के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए समय–सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में सड़क संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने में तेजी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति मिलेगी।

बैठक

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2026–27 की वार्षिक कार्य योजना को लेकर राज्य स्तरीय संस्तुति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति ने वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में आधार आधारित भुगतान और ई–केवाईसी को प्रभावी ढंग से लागू करने की बात कही गई। मुख्य सचिव ने किसान उत्पादक संगठन बनाकर क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा देने, जैविक और प्राकृतिक खेती के प्रयास तेज करने और अधिक संख्या में फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के निर्देश दिए।

श्री बर्द्धन ने अगली राज्य स्तरीय संस्तुति समिति की बैठक दिसंबर–जनवरी में आयोजित करने को कहा। उन्होंने किसान मानधन योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार और अधिक से अधिक पात्र किसानों के पंजीकरण पर जोर दिया। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शत–प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए।

सतर्कता

राज्य के पर्वतीय जिलों में बर्फबारी और हिमस्खलन की संभावना को देखते हुए सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से जारी सूचना के अनुसार आज प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और हिमस्खलन की आशंका जताई गई है।

विशेष रूप से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों को अधिक संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जबकि रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भी हिमस्खलन की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बर्फबारी और हिमस्खलन की स्थिति में अनावश्यक आवाजाही से बचें और मौसम की जानकारी लेते रहें।

इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन करने को कहा गया है, ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके।

एस.आई.आर तैयारियां

प्रदेश में अप्रैल माह में होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस प्रक्रिया में अब बूथ लेवल अधिकारियों की मदद के लिए आईटी वॉलंटियर्स भी तैनात किए जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सचिवालय में एसआईआर को लेकर नोडल अधिकारियों की बैठक ली तथा तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सभी बूथों पर तकनीकी रूप से दक्ष वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे, जो गणना प्रपत्र के डिजिटलाइजेशन के साथ–साथ उनके वितरण और संकलन में भी सहयोग करेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि इस अभियान के लिए जल्द तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं को जोड़ा जाए। इसके साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में मैपिंग कार्य पर विशेष ध्यान देने को भी कहा गया है।

प्रेस वार्ता

केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। घरेलू एलपीजी उत्पादन स्थिर है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। नई दिल्ली में कल पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर–मंत्रालयी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में उपभोक्ताओं को 11 हजार 300 टन व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति की गई है। उन्होंने कहा कि घरेलू एलपीजी उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और खुदरा दुकानों पर एलपीजी की कोई कमी नहीं है।

सुश्री शर्मा ने बताया कि प्रीमियम पेट्रोल की दरों में मामूली वृद्धि हुई है जबकि सामान्य पेट्रोल की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

परीक्षण

उत्तराखंड में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कल परीक्षण अलर्ट जारी किया गया। यह पहल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से की जा रही है, जिसका उद्देश्य संभावित आपदाओं से पहले लोगों को समय पर सतर्क करना है।

प्राधिकरण की ओर से जारी इस परीक्षण का उद्देश्य आपातकालीन सूचना प्रसारण प्रणाली की कार्यक्षमता को परखना है, ताकि आपदा की स्थिति में अलर्ट संदेश समय पर और व्यापक रूप से लोगों तक पहुंच सके।

अधिकारियों के अनुसार इस प्रणाली के परीक्षण अगले एक सप्ताह तक जारी रहेंगे। इस दौरान विभिन्न मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से भेजे जा रहे अलर्ट संदेशों की पहुंच और प्रभावशीलता का आकलन किया जाएगा और जहां जरूरत होगी वहां सुधार किया जाएगा।

प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे परीक्षण अलर्ट को लेकर किसी प्रकार की अफवाह या घबराहट में न आएं और प्रशासन के दिशा–निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था भविष्य में आपदा के दौरान नुकसान को कम करने में मददगार साबित होगी।